Proportion of Suzuki and Government shares in MUL

572. SHRI S. AUSTIN:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI V. HANUMANTHA RAO:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the proportion of shares of Suzuki Motor Company and that of Government of India in the shares of Maruti Udyog Ltd.;

(b) whether Maruti Udyog Limited has received any proposal to go for disinvestment as well as for new issue; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) The pattern of shareholding of Maruti Udyog Ltd. is as under:

Suzuki Corporation	Motor— 50%
Government of India	— 4974%

(b) Government has not received any proposal from Maruti Udyog Ltd. for disinvestment of shares or for new issue.

(c) Does not arise.

Reduction in JRY Targets

573. CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:
SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the target of Jawahar Rojgar Yojana for the year 1995-96 has been reduced in comparison to that of the year 1994-95;

(b) if so, what are the reasons for this reduction;

(c) whether it is also a fact that even the amount allocated for this has not been spent; and

(d) if so, what is the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) Yes, Sir. The physical target for the year 1995-96 under the Jawahar Rozgar Yojana has been set at 9054.74 lakh mandays as compared to the target of 9865.45 lakh mandays which was set for the year 1994-95. The physical target under the JRY is set at the beginning of the financial year after taking into account the resource availability and also the minimum wage rates prevalent in different states. The increase in the wages as also the material component has to be completely absorbed within the funds allotted for the scheme for the year. The minimum wage rates in several major states such as Madhya Pradesh, Uttar pradesh, Andhra Pradesh, and Haryana etc. increased during the year 1994-95. The physical targets in terms of mandays for the year 1995-96 were thus fixed after taking into account the increse the likely expenditure on account of the revision in the minimum wages.

(c) and (d) No, Sir. During the year 1994-95 all the States and UTs together utilized Rs. 4268.33 crores under the JRY against a total outlay (Centre plus State share) of Rs. 4376.92 crores. This works out to 78.80% of the total funds available and 97.52% of the total funds allocated during the year 1994-95.

वापी गुजरात में क्लोरीन फैक्ट्री स्थापित किया जाना

574. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के वापी औद्योगिक परिसर में नार्वे की सहायता से एक नई क्लोरीन फैक्ट्री स्थापित की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इसके उत्पादन की खतरनाक प्रक्रिया से प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण नार्वे की सरकार ने नार्वे में इस उद्योग पर

प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस उद्योग में क्लोरीन का उत्पादन करने के कार्य को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर, तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ): प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात के वापी औद्योगिक परिसर में नार्वे की सहायता से कोई भी क्लोरीन फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों में भारतीय सैनिक

575. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में सम्मिलित किए गए भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्रवाइयों में मारे गये सैनिकों की मिशन-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो मिशन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, जिन्हें अभी मुआवजे का भुगतान किया जाना है अथवा जिन्हें इस मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 21 जुलाई, 1995 की स्थिति के अनुसार कुल 2047 भारतीय रक्षा कार्मिकों (सभी रैंक) को विदेश में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के विभिन्न मिशनों में तैनात किया गया था।

(ख) विगत 3 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना कार्रवाइयों में कम्बोडिया में 4, मोजाम्बिक में 2 और सोमालिया में 14 भारतीय रक्षा कार्मिक मारे गए।

(ग) सभी दिवंगत सैन्य कार्मिकों के परिवारों को परिवार पेंशन और उपदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

युद्ध अथवा युद्ध सदृश संक्रियाओं में मारे जाने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों के परिवारों को उन सेना कार्मिकों द्वारा अंतिम बार प्राप्त की गई गणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन तथा सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर परिवार उपदान दिया जाता है। इसके अलावा ये परिवार अनुकंपा के आधार पर रोजगार तथा सेना सामूहिक बीमा योजना आदि के तहत लाभ सहित विभिन्न लाभ पाने के भी हकदार हैं।

संयुक्त राष्ट्र, भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्रवाइयों में मारे जाने वाले सैन्य कार्मिकों को अदा की जाने वाली पेंशन संबंधी राशि की राष्ट्रीय करनून के अनुसार प्रतिपूर्ति करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ उसके महासचिव द्वारा यह निर्धारित करने पर कि मृत्यु, घायलावस्था या बीमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की जाने वाली ड्यूटियों के कारण हुई है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों को अधिकतम 50,000 अमरीकी डालर अथवा संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों के भत्तों रहित वार्षिक बेस वेतन की दुगनी राशि, इनमें से जो भी कम हो, की मुआवजे के रूप में अदायगी करता है।

Essential Supplies/Financial Assistance in J&K

576. **SHRI RAMDAS AGARWAL:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether government are aware that the major amount/quantum of the financial assistance/essential supplies which is intended for the development purposes of Jammu and Kashmir is being grabbed/forcibly snatched by militants;

(b) whether Governemnt's attention has been drawn to a press release issued in Jammu on 16th July, 1995 by Defence authorities saying "in a strange move, the J&K traffic police have stopped the movement of army-hired civil trucks carrying day-to-day essential items for soldiers deployed in the Kashmir Valley and far-flung areas of Ladakh region"; and

(c) if so, what preventive measures Government propose to take to ensure that all central assistance/supply of essential items reach the hands of needy?